

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 15

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1507.14	42.67	1549.81	2820.50	52.00	2872.50	1727.51	51.60	1779.11	3050.00	57.00	3107.00	
पूँजी	142.87	...	142.87	179.50	...	179.50	141.49	...	141.49	265.00	...	265.00	
जोड़	1650.01	42.67	1692.68	3000.00	52.00	3052.00	1869.00	51.60	1920.60	3315.00	57.00	3372.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	40.34	25.83	66.17	45.00	32.30	77.30	40.00	33.17	73.17	48.89	37.30	86.19
दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग													
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	2852	90.38	...	90.38	92.61	...	92.61	92.61	...	92.61	90.50	...	90.50
	3451	523.40	...	523.40	528.39	...	528.39	456.00	...	456.00	529.50	...	529.50
	5475	133.87	...	133.87	126.00	...	126.00	117.49	...	117.49	100.00	...	100.00
जोड़	747.65	...	747.65	747.00	...	747.00	666.10	...	666.10	720.00	...	720.00	
3. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (आईटीआरए सहित)	2852	47.00	...	47.00	81.00	...	81.00	49.10	...	49.10	54.00	...	54.00
4. शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क (ईआरएनईटी)	2852	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम	2852	23.05	0.09	23.14	29.00	0.60	29.60	23.00	0.60	23.60	27.00	0.60	27.60
6. सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम एनएमसी	2852	37.89	...	37.89	100.00	...	100.00	57.00	...	57.00	100.00	...	100.00
7. उन्नत परिकलन विकास केंद्र (सी-डैक)	2852	110.53	3.00	113.53	184.00	3.00	187.00	101.00	3.00	104.00	153.00	3.00	156.00
8. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	2852	42.71	3.00	45.71	48.00	3.00	51.00	48.00	3.00	51.00	50.00	3.00	53.00
9. मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	2852	60.79	6.36	67.15	81.00	7.00	88.00	67.95	7.00	74.95	85.00	7.00	92.00
	4859	4.67	...	4.67	29.00	...	29.00	4.00	...	4.00	25.00	...	25.00
जोड़	65.46	6.36	71.82	110.00	7.00	117.00	71.95	7.00	78.95	110.00	7.00	117.00	
10. एकीकृत नगर क्षेत्र की स्थापना का सरलीकरण	2852	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
11. जनशक्ति विकास (जनसामान्य के लिए आईटी एवं आईटी में कौशल विकास सहिता	2852	103.52	...	103.52	90.00	...	90.00	54.50	...	54.50	110.00	...	110.00
12. अभिकरण, संचार एवं युद्धनीतिक इलेक्ट्रॉनिकी	2852	24.99	...	24.99	28.00	...	28.00	15.75	...	15.75	27.00	...	27.00
13. स्वास्थ्य और दूरऔषध में इलेक्ट्रॉनिकी	2852	3.16	...	3.16	9.00	...	9.00	7.75	...	7.75	8.00	...	8.00
14. अन्य कार्यक्रम													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14.01 इलेक्ट्रानिकी प्रदर्शनी	2250	...	0.59	0.59	...	0.80	0.80	
14.02 विदेशी व्यापार	3453	...	2.00	2.00	...	3.10	3.10	...	2.73	2.73	...	3.10	
14.03 अन्य स्कीमें	2852	...	0.10	0.10	...	0.50	0.50	...	0.40	0.40	...	1.30	
जोड़- अन्य कार्यक्रम	2.69	2.69	...	4.40	4.40	...	3.13	3.13	...	4.40	
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	281.00	...	281.00	199.50	...	199.50	247.00	...	247.00
	4552	19.00	...	19.00	14.50	...	14.50	15.00	...	15.00
जोड़	300.00	...	300.00	214.00	...	214.00	262.00	...	262.00
16. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस													
16.01 कार्यक्रम घटक	2852	336.95	...	336.95	530.00	...	530.00	317.45	...	317.45	97.00	...	97.00
16.02 ईएपी घटक	2852	80.00	...	80.00	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
जोड़- इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस	...	416.95	...	416.95	630.00	...	630.00	377.45	...	377.45	197.00	...	197.00
17. भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास	2852	18.57	...	18.57	34.00	...	34.00	18.00	...	18.00	24.00	...	24.00
18. साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, आईटी अधिनियम सहित)	2852	26.54	...	26.54	47.87	...	47.87	36.87	...	36.87	114.00	...	114.00
	4859	4.33	...	4.33	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	115.00	...	115.00
जोड़	...	30.87	...	30.87	53.37	...	53.37	42.37	...	42.37	229.00	...	229.00
19. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और ईएचटीपी	2852	1.88	...	1.88	52.50	...	52.50	4.20	...	4.20	10.00	...	10.00
20. जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	2852	7.03	...	7.03
21. इलेक्ट्रॉनिक विभाग अधिकृत प्रमाणन पाठ्यक्रम (डीओईएसीसी)	2852	8.80	1.70	10.50	9.75	1.70	11.45	8.75	1.70	10.45	9.00	1.70	10.70
22. इलेक्ट्रॉनिकी/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन	2852	4.89	...	4.89	100.00	...	100.00	10.00	...	10.00	90.00	...	90.00
	4859	10.00	...	10.00
जोड़	...	4.89	...	4.89	100.00	...	100.00	10.00	...	10.00	100.00	...	100.00
23. राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र	2852	122.19	...	122.19	320.00	...	320.00	312.23	...	312.23	261.00	...	261.00
24. मीडिया लैब एशिया	2852	23.27	...	23.27	12.75	...	12.75	7.00	...	7.00
25. कंट्रोलर ऑफ सर्टीफिकिंग आथारिटीस (सीसीए)	2852	2.40	...	2.40	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
26. वास्तविक वसूलियां	2852	-209.84	...	-209.84	-271.00	...	-271.00
	3451	-0.03	...	-0.03
जोड़	...	-209.87	...	-209.87	-271.00	...	-271.00
जोड़-दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र योजना		1609.67	16.84	1626.51	2955.00	19.70	2974.70	1829.00	18.43	1847.43	2466.11	19.70	2485.81
27. नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (एनईजीएपी)	2552	70.00	...	70.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3601	680.00	...	680.00	
3602	50.00	...	50.00	
जोड़	800.00	...	800.00	
कुल जोड़	1650.01	42.67	1692.68	3000.00	52.00	3052.00	1869.00	51.60	1920.60	3315.00	57.00	3372.00	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
0.01 समीर/सी-डैक-आदि	12859	...	651.43	651.43	...	742.59	742.59	...	666.07	666.07	...	795.78	795.78
जोड़		...	651.43	651.43	...	742.59	742.59	...	666.07	666.07	...	795.78	795.78
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	1086.30	651.43	1737.73	2126.61	742.59	2869.20	1159.00	666.07	1825.07	1674.61	795.78	2470.39
2. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	563.71	...	563.71	573.39	...	573.39	496.00	...	496.00	578.39	...	578.39
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	300.00	...	300.00	214.00	...	214.00	262.00	...	262.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		1650.01	651.43	2301.44	3000.00	742.59	3742.59	1869.00	666.07	2535.07	2515.00	795.78	3310.78
राज्य योजना:													
1. राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (एनईजीएपी)	43601	750.00	...	750.00
जोड़ - राज्य योजना		750.00	...	750.00
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (एनईजीएपी)	43602	50.00	...	50.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		50.00	...	50.00
जोड़		1650.01	651.43	2301.44	3000.00	742.59	3742.59	1869.00	666.07	2535.07	3315.00	795.78	4110.78

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएँ:** इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी):** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का संबद्ध कार्यालय है। यह देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघशासित क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों को नेटवर्क बैकबोन और ई-शासन सहयोग प्रदान कर रहा है। यह नेटवर्क मूलसंरचना सुविधा प्रदानकर्ता, नेटवर्क सेवा

प्रदानकर्ता, अनुप्रयोग सेवा प्रदानकर्ता तथा सूचना सामग्री एएसपी है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 20.00 और 70.50 करोड़ रुपए है, शामिल हैं।

3. **प्रौद्योगिकी विकास परिषद् कार्यक्रम (आईटीआरए सहित):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को सहयोग देकर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का प्रसार और आत्मसात् करने की सुविधा प्रदान करना: निशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना: महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अद्यतन तकनीकी जानकारी के

किफायती स्वदेशी समाधानों का विकास करना एवं लागू करना: जैव सूचना विज्ञान में प्रौद्योगिकी विकास, आईपीआर संवर्धन, नवोदभव तथा उदभव संवर्धन और सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और आवेदन सहित) की स्थापना करना है।

4. **शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट):** भारत यह आईपीवी 6 पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जिसके पांच संकेद्रित क्षेत्र हैं: राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान नेटवर्क; आंकड़ा संचार और इसके अनुप्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास; उच्च स्तरीय नेटवर्किंग के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास; शैक्षणिक सूचना सामग्री तथा परिसर व्यापी उच्चगति का स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क।

5. **संघटक पुर्जा एवं सामग्री विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री के लिए ठोस अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकीय आधार तैयार करना तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना और अनुसंधान एवं विकास के समुचित संस्थानों और उद्योग में महत्वपूर्ण और प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री के लिए लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान एवं विकास की परियोजनाओं को सहयोग देना।

6. **सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी और नैनो प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग में जनशक्ति, अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के लिए ठोस आधार का निर्माण करना है तथा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए अनुप्रयोग विशिष्ट एकीकृत परिपथों (एसिक) के इस्तेमाल को बढ़ावा और प्रसार करना है। यह एसआईसीएलडीआर का भी समर्थन करता है।

7. **उच्च अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक):** यह अभिकलन और संचार तथा इससे उत्पन्न अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है।

8. **प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी और अनुसंधान संस्था (समीर):** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो सूक्ष्म तरंग, मिली मीटर तरंग और इलेक्ट्रो चुम्बकीयता के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्य कर रही है जो मुम्बई, चेन्नै तथा कोलकाता स्थित अपने तीन केन्द्रों सहित इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोगों का विकास करने के विशिष्ट लक्ष्य से कार्य कर रही हैं।

9. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** सरकारी निदेशालयसूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स संघटक-पुर्जों और उत्पादों की क्वालिटी और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए उद्योग को परीक्षण और अंशानकन सेवाएं प्रदान करता है।

10. **एकीकृत टाउनशिप की स्थापना सुकर करना:** एकीकृत अत्याधुनिक मूलसंरचना द्वारा निरूपित किए जाते हैं तथा राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

11. **जनशक्ति विकास (सूचना प्रौद्योगिकी में कुशलता विकास/जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहित):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की

उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पहलों में औपचारिक क्षेत्र से उभरते हुए अंतरालों की पहचान करना और इन अंतरालों को दूर करने के लिए औपचारिक और औपचारिक क्षेत्रों में आयोजना कार्यक्रम शामिल हैं। इस बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) तथा आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत क्रमशः 3 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

12. **समाहार, संचार एवं सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स:** इसका उद्देश्य समाहार संचार, ब्रांडबैण्ड प्रौद्योगिकियों तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान एवं विकास की सहायता प्रदान करना है। स्वदेशी प्रयासों का लक्ष्य देश में समाहारी और स्थाई वृद्धि के लिए उदीयमान, अगली पीढी के समाहार संचार, ब्रोड बैंड तथा प्रसारण एवं सामरिक प्रौद्योगिकियों में विकास कार्य की सुविधा प्रदान करना है।

13. **चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान में अनुसंधान और विकास (तत्कालीन स्वास्थ्य व चिकित्सा में इलेक्ट्रॉनिक्स):** इसका उद्देश्य चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान एवं विकास का समर्थन और बढ़ावा देने के लिए है।

14. **अन्य स्कीम:** ये गैर-योजना प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क(एसटीपी) यूनितों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार केन्द्रीय विक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ सम्मेलन संगोष्ठी आयोजित करने और विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार आदि के लिए सहायता प्रदान करने हेतु किए गए हैं।

15. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान:** सरकार के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय योजनागत आबंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ योजना के लिए निर्धारित किया जाना है।

16. **इलेक्ट्रॉनिक शासन:** व्यापक अर्थ में इलेक्ट्रॉनिक शासन का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाएँ साधारण जनता को उन्हीं के इलाकों में उपलब्ध कराना है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 10 और 30 करोड़ रुपए है, शामिल हैं।

17. **भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी, सभी उपकरणों और मानक का विकास करना है जिससे कि सभी स्टेकहोल्डर कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग अपनी भाषाओं में करने में सक्षम बन सकें।

18. **साइबर सुरक्षा (सर्ट-इन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित):** सभी प्रकार के उत्पादों में विभिन्न कारणों से चथा राष्ट्रीय सुरक्षा असुरक्षा की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण सुरक्षित उत्पादों के विकास, कार्यानिष्पादन तथा लागत संबंधी दण्ड, उपभोक्ताओं की सहजता में सुधार, सुरक्षा प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने तथा निरन्तर रूप से उन्हें बनाए रखने और सुरक्षा में सुधार के मूल्यांकन के महत्व के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता में बढ़ोत्ती से साइबर सुरक्षा को अपनाया जा रहा है। है। भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर कार्रवाई करने और उनके दोहराव से बचने के उपाय करने के लिए कार्य कर रहा है और आवश्यकतानुसार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। प्रमाणन प्राधिकारियों को सीसीए द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।

19. **आईटी / आईटीईएस उद्योग की पदोन्नति (पूर्व भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) तथा ईएचटीपी):** इस स्कीम को पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीसीआई) और ईएचटीपी के नाम से जाना जाता था आईटी-आईटीईएस उद्योग का वैश्विक परिदृश्य तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। भारत की नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए, आईटी-आईटीईएस उद्योग, खासकर छोटे आईटी इकाइयों, के विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समर्थन की जरूरत है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना संचार सम्पर्कों का प्रयोग करके या वास्तविक माध्यम से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास और निर्यात के लिए एक शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है जिसमें व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भी शामिल है। एसटीपी योजना सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में तेजी लाने में बहुत ही सफल रही है इस समय एसटीपीआई के 53 केन्द्र पूरे देश में स्थित हैं जिनमें से 45 केन्द्र स्तर 2 तथा स्तर 3 के शहरों स्थित हैं।

21. **एनआईईएलआईटी:** यह विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों/संगठनों को प्रत्यायित करती है। यह अद्यतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के उद्योग उन्मुखी शिक्षण एवं प्रशिक्षण का विकास भी करती है, आईसीटी के क्षेत्र में परीक्षा एवं प्रमाणन के लिए देश का अग्रणी संस्थान बनाने के लिए मानक निर्धारित करती है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जिसमें प्रत्येक के लिए 1 करोड़ और 2 करोड़ शामिल है।

22. **इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र के विकास की आला क्षेत्र में पहचान की है जिसे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार की पूर्ति हेतु एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और विनिर्माण उद्योग के संवर्धन में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर नई राष्ट्रीय नीति के रूप में स्पष्ट किया गया है।

23. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** यह योजना पूरे देश के ज्ञान संस्थानों को आपस में बहु गीगाबिट बैंडविड्थ से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के प्रयोजन से शुरू की गई है। इसके बजट प्रावधान में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) जो क्रमशः 8 और 25 करोड़ रूपए है, शामिल हैं।

24. **मीडिया लैब एशिया:** मीडिया लैब एशिया एक धारा 25 कंपनी है जिसका उद्देश्य अति उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लाभ को सामान्य जनता तथा जरूरत मंद लोगों तक पहुंचाना है।

25. **प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए):** प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक (सीसीए) का कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 17 के तहत बनाया गया है। सीसीए के विभिन्न कार्यों में लाइसेंस, पर्यवेक्षण और प्रमाणन प्राधिकरण की निगरानी, प्रमाणन प्राधिकरण लोक कुंजी प्रमाण पत्र और डिजिटल हस्ताक्षर / पीकेआई पर जागरूकता कार्यक्रम बनाना शामिल है। लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकरण विभिन्न ग्राहकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है। इसका विभिन्न ई शासन सक्षम अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका प्रमुख उपयोग, आयकर रिटर्न दाखिल, कंपनी के पंजीकरण, ई-निविदा/ई-खरीद ई फाइलिंग, ई पी ओ, ई - मेल पर हस्ताक्षर करने और एन्क्रिप्शन, ई बैंकिंग और ई प्रमाणीकरण में है।

27. **राष्ट्रीय ई शासन कार्य योजना:** 12 वीं योजना में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप, एनईजीएपी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) देने के लिए स्वीकार किया गया है। इसकी पहल, राज्य भर में क्षमता निर्माण का निर्माण सरकारी सेवाओं को एकीकृत और बढ़िया पहुँच प्रदान करने, राज्य डाटा केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है।